HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 21.6.2024
Page No. 3, Size:(18.53)cms X (7.78)cms.

NHRC notice to Hry after 2 die cleaning septic tank

Press Trust of India
letterschd@hindustantimes.com

NEW DELHI : The NHRC has sent notices to the Haryana government and the state's police chief over reports that two brothers died allegedly after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory in Sonepat district.

The "negligence" of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were "not provided any safety gear" while cleaning the septic tank, the National Human Rights Commission said in a statement.

The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report, carried on June 13, 2024, that two brothers died after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory near the village Bazidpur Saboli in the district Sonepat, Haryana".

Their third companion from the same village has reportedly survived the accident, it said.

The police authorities have sent the bodies of the deceased for post-mortem examination and an FIR has been registered against the factory owner, the statement said.

The commission has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of violation of human rights.

"The negligence of the factory owner and the local authorities

RESPONSE SOUGHT FROM HARYANA GOVERNMENT AND DGP OVER JUNE 13 INCIDENT WHEN SIBLINGS DIED WHILE CLEANING SEPTIC TANK OF A SONEPAT FACTORY

is apparent, as reportedly, the workers were not provided any safety gear while cleaning the septic tank.

"This even though the commission has been reiterating the implementation of its advisory dated September 24, 2021, and guidelines of the apex court to end manual hazardous cleaning by using machines and providing safety equipment to the workers," the statement said.

Accordingly, the commission has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Haryana, seeking a detailed report in one week including the status of the FIR registered, action taken against persons responsible as well as relief and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased workers by the authorities, it said.

Issuing the notices, the commission has drawn the attention of the authorities concerned in its advisory on the Protection of Human Rights of the Person Engaged in Manual Scavenging or Hazardous Cleaning.

It is mentioned that in case of the death of any sanitary worker, while undertaking hazardous cleaning work, the local authority and the contractor or employer are to be held responsible and accountable, jointly and severally, irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary worker, the statement said.

"Apart from this, the decision is given by the Supreme Court, Dr Balram Singh vs Union of India (WP(C) No. 324 of 2020) dated 20.10.2023, provides the specific mandate that it is the duty of the local authorities and other agencies to use modern technology to clean sewers," it added.

DAINIK JAGRAN, Faridabad, 21.6.2024
Page No. 6, Size:(7.99)cms X (7.24)cms.

सेप्टिक टैंक सफाई में मौत पर मानवाधिकार आयोग का मुख्य सचिव-डीजीपी को नोटिस

- सोनीपत में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी टैंक की सफाई के दौरान
- कहा-गाइडलाइन का पालन अधिकारियों की जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, सोनीपत : गांव वाजिदपुर सबौली स्थित एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि फैक्ट्री मालिक और अधिकारियों की लापरवाही के चलते सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। यह तब है, जब आयोग मशीनों का उपयोग कर मैन्युअल सफाई को समाप्त करने और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए 24 सितंबर, 2021 में आदेश दे चुका है और शीर्ष अदालत भी इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दुर्घटना में ठेकेदार व नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। भले ही सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रकार कुछ भी हो।

कार्रवाई करने की रिपोर्ट मांगी: आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें एफआइआर की स्थिति, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा मृत श्रमिकों के स्वजनों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की जानकारी होनी चाहिए। आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डा. बलराम सिंह बनाम यूनियन आफ इंडिया के 20 अक्टूबर, 2023 को दिया गया निर्णय विशिष्ट आदेश प्रदान करता है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई कि सीवर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए।

AMAR UJALA, Delhi, 21.6.2024
Page No. 10, Size:(5.20)cms X (3.88)cms.

सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त दो भाइयों की मौत पर राज्य सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली। हरियाणा के सोनीपत जिले के बाजिदपुर सबोली गांव के पास एक निजी पैकेजिंग फैक्टरी में दो भाइयों की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दोनों भाइयों की सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त जहरीली गैस से मौत हो गई थी।

आयोग ने इस घटना की 13 जून की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में दर्ज एफआईआर की स्थिति, घटना के जवाबदेह लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों के मृतक श्रमिकों के परिजनों दी गई राहत और पुनर्वास की जानकारी देनी होगी। एजेंसी

VIRAT VAIBHAV, Delhi, 21.6.2024
Page No. 5, Size:(2.50)cms X (7.38)cms.

एनएचआरसी ने गलत घुटने का ऑपरेशन किए जाने पर हरियाणा सरकार, डीजीपी को नोटिस दिया

नई दिल्ली। हरियाणा के पानीपत के एक अस्पताल में मरीज के दाहिने घुटने के स्थान पर कथित तौर पर बाएं घुटने का ऑपरेशन किए जाने की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि खबर के अनुसार अस्पताल ने आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होने के बावजूद मरीज से शुल्क भी वसूला। आयोग ने इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया कि पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के चोटिल दाहिने घुटने के स्थान पर उसके बाएं घुटने का कथित रूप से ऑपरेशन कर दिया गया। बयान के अनुसार खबरों में यह भी कहा गया है जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया।

AMAR UJALA, Delhi, 21.6.2024
Page No. 10, Size:(5.28)cms X (6.72)cms.

मरीज के गलत घुटने की सर्जरी पर एनएचआरसी ने मांगा जवाब

हरियाणा के पानीपत के एक मरीज का दाएं की जगह बाएं घुटने का किया था ऑपरेशन

नई दिल्ली। हरियाणा के पानीपत में एक मरीज के दाएं की जगह बाएं घुटने का ऑपरेशन करने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब तलब किया है। अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।आयोग ने कहा कि उसने इस मसले पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया है।

इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और यदि मरीज कोई मुआवजा दिया गया है तो उसका ब्यौरा भी देने को कहा गया है। आयोग ने अपने बयान में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद मरीज से अस्पताल ने 8,000 रुपये का शुल्क लिया और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी छीन लिया। मरीज के परिजनों के विरोध करने पर डॉक्टरों ने तुरंत मरीज के चोटिल की जगह सही घुटने की सर्जरी कर दी। इससे मरीज चलने में असमर्थ हो गया।

पीड़ित ने 2006 में एक हादसे में अपना परिवार को खो दिया था। इसके बाद से ही वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। घर की सफाई के दौरान गिरने से उसका दाहिना घुटना चोटिल हो गया था। एजेंसी

DAINIK JAGRAN, Delhi, 21.6.2024
Page No. 8, Size:(3.84)cms X (3.16)cms.

मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

जासं, सोनीपत: गांव वाजिदपुर सबौली स्थित एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं दिए गए, मशीनों का उपयोग करने और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए 24 सितंबर 2021 को आदेश दिया गया था।

अमेजन ऑफिस हैया जेल, टॉयलेट जानेऔर पानी पीनेपर पाबंदी, मानवाधिकार आयोग का केंद्र सरकार को नोटिस

https://www.livehindustan.com/business/amazon-employees-do-not-get-toilet-breaks-human-rights-commission-issues-notice-to-central-government-201718848420902.html

Amazon Employee news: हरियाणा के मानेसर मेंअमेजन इंडिया के गोदाम सेजुड़ी ऐसी एक न्यूज रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेतेहुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेकेंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

अमेजन अपनेकर्मचारियों को कथित तौर पर टायलेट ब्रेक भी नहीं देता। हरियाणा के मानेसर मेंअमेजन इंडिया के गोदाम सेजुड़ी ऐसी एक न्यूज रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेतेहुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेकेंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आयोग नेकहा कि अगर रिपोर्ट सच है, तो यह श्रम कानूनों का उल्लंघन है।

टीओआई की खबर के मुताबिक रिपोर्ट मेंमजदूरों नेकहा कि उनसेयह शपथ कराई गई कि जब तक उनका काम का टार्गेट पूरा नहीं हो जाता, वेन तो टॉयलेट ब्रेक लेंगेऔर न ही वॉटर ब्रेक। इस केस की प्रोसिडिंग के मुताबिक, "हरियाणा के मानेसर मेंअमेजन इंडिया के एक गोदाम में 24 वर्षीय एक मजदूर सेयह प्लेज करानेको कहा गया कि जब तक वह 24 फीट लंबे 6 ट्रकों सेसारेपैकेज उतार नहीं लेता, तब तक वह शौचालय नहीं जाएगा और न ही पानी का ब्रेक लेगा, जब तक कि उनकी टीम का 30 मिनट का टी ब्रेक समाप्त नहीं हो जाता"। "शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं" इस मामलेकी कार्यवाही में 16 मई को एक टीवी चैनल पर आई रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमेंदिखाया गया कि पिछले महीनेगोदाम की 'इनबाउंड टीम' ने 8 बार शपथ ली थी। कर्मचारियों नेइसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट मेंकहा गया हैकि गोदाम से निकलनेवालेसामानों को हैंडल करनेवाली 'आउटबाउंड टीम' को रोजाना उसके टार्गेट की याद दिलाई जाती थी। मानेसर गोदाम में एक महिला कर्मचारी नेकथित तौर पर कहा कि काम करनेवाली जगहों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

नियमों का उल्लंघन करनेका आरोप

रिपोर्ट के मुताबिक भारत मेंश्रमिक संघों नेमानेसर और उसके आसपास के पांच गोदामों पर कारखाना अधिनियम, 1948 में उल्लि खित नियमों का उल्लंघन करनेका आरोप लगाया है। खबरों मेंकहा गया हैकि सप्ताह में 5 दिन रोजाना 10 घंटे काम करने वाला कर्मचारी एक दिन मेंचार ट्रक सेअधिक सामान नहीं उतार सकते। वह भी तब जब 30 मिनट के लंच और टी ब्रेक सहित बिना ब्रेक के लगातार काम करतेहों। एक महिला कर्मचारी नेदावा किया कि वह रोजाना 9 घंटे खड़ी रहती ह

क्या कह रहा अमेजन

लिए डिजाइन की गई हैं। इंप्लाई और एसोसिएट्स अपनी शिफ्ट के दौरान अनौपचारिक ब्रेक लेनेके लिए स्वतंत्र हैंताकि वे शौचालय का उपयोग कर सकें, पानी लेसकें या किसी मैनेजर या एचआर सेबात कर सकें।"

Amazon में कर्मचारियों के टॉयलेट जाने और पानी पीने पर पाबंदी! केंद्र सरकार से मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

https://www.patrika.com/national-news/amazon-employees-are-banned-from-going-to-the-toilet-and-drinking-water-human-rights-commission-seeks-response-from-the-central-government-18784265

No Toilets Breaks in Amazon India: अमेजन इंडिया पर कर्मचारियों को टॉयलेट जाने और पानी पीने तक का ब्रेक नहीं देने का आरोप लग रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

Amazon India bans toilets and drink water to his staff: चीन में कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को बंधक बनाकर काम करवाने की खबरें बहुत बार सुर्खियां बनी हैं लेकिन इस बार इससे मिलती-जुलती खबर भारत के हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के मानेसर स्थित अमेजन इंडिया **(Amazon India, Manesar)** पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अपने कर्मचारियों को टॉयलेट ब्रेक **(No Toilets Breaks)** तक नहीं दे रहा है। यहां अमेजन का गोदाम है। इस खबर का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर यह रिपोर्ट ठीक है तो यह बेहद खराब बात है।

कर्मचारी को खिलाई कसम, ना पानी पीएंगे, ना ही टॉयलेट बेक लेंगे

मानेसर स्थित अमेजन इंडिया ने मीडिया को बताया कि उनके मैनेजर ने उन्हें यह कसम खिलाई कि वे जब तक अपना टार्गेट पूरा नहीं करेंगे तब तक किसी तरह का ब्रेक नहीं लेंगे। वे न तो टॉयलेट जाएंगे और न ही पानी पीएंगे। ऐसा बताया गया कि मानेसर में अमेजन इंडिया के मजदूरों को यह कसम खिलाई गई कि जबतक 24 फीट लंबे 6 ट्रकों से सभी पैकेट नहीं उतार लिए जाएं तब तक वे ना ही शौचालय जाएंगे और ना ही पानी पीने के लिए ब्रेक लें। यह भी बताया गया कि मामला अदालत में चल रहा है।

कर्मचारियों पर टार्गेट पूरा करने का पूरा दबाव बनाती है कंपनी

अमेजन के गोदामों में दो तरह की टीमें काम करती हैं- 1. इनबाउंड और 2. आउटबाउंड टीम। टीवी चैनल पर यह रिपोर्ट दिखाया गया कि पिछले महीने गोदाम की इनबाउंड टीम ने 8 बार इस तरह की शपथ ली। इस बात की पुष्टि यहां कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों ने कर दी है। वहीं यह बताया गया कि गोदाम से सामान बाहर निकालने वाली टीम को भी इसी तरह की कसमें खिलाई जाती हैं और उन्हें रोज उनके टार्गेट याद दिलाए जाते हैं। महिला कर्मचारियों का आरोप यह है कि गोदाम जहां वो काम करती हैं वहां शौचालय तक की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

अमेजन पर लग रहा है नियमों के उल्लंघन का आरोप

भारत में मजदूर और कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले मजदूर संघ भी यह आरोप लगा रहे हैं कि मानेसर के पांच गोदामों में कारखाना अधिनियम 1948 का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। कारखाना अधिनियम के मुताबिक, किसी भी कारखाना या फैक्ट्री में एक मजदूर सप्ताह में 5 दिन रोजाना 10 घंटे काम करने वाला मजदूर एक दिन में चार ट्रक से अधिक सामान की अनलोडिंग नहीं कर सकते हैं। इतना काम भी तब करवाया जा सकता है जब मजदूरों को 30 मिनट के लिए लंच और टी ब्रेक नहीं दिया गया हो। महिला मजदूर और कर्मियों का हाल तो और भी बुरा है। एक महिला कर्मचारी ने बताया कि उन्हें हर रोज 9-10 घंटे तक खड़े ही रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पीरियड्स के दिनों में यह सबकुछ असहनीय हो जाता है।

हमारे यहां कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ख्याल

हालांकि इससे उलट अमेजन इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि हमारे कर्मचारियों और सहयोगियों की सुरक्षा और भलाई कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह दावा करते हैं उनके यहां कर्मचारियों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है। उनका कहना है कि कोई भी कर्मचारी अपनी शिफ्ट के दौरान ब्रेक लेने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि वह पानी पी सकें और शौचालय जा सकें।

Amazon के गोदाम बने जेल! टार्गेट पूरा होने से पहले नहीं जा सकते टॉयलेट, पानी पीने पर भी पाबंदी!

https://www.morningnewsindia.com/business/news/nhrc-issues-notice-to-india-govt-for-amazon-employee-rights-violation/

जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने Amazon India के गोदामों से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस में अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों संग हो रहे व्यवहार तथा वहां की परिस्थितियों को लेकर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।

TOI की रिपोर्ट पर लिया नोटिस

हाल ही टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेजन इंडिया के गोदामों में मजदूरों से शपथ कराई गई थी वे अपना टारगेट पूरा नहीं होने तक टॉयलेट ब्रेक और वॉटर ब्रेक नहीं लेंगे। एक 24-वर्षीय मजदूर ने भी कहा था कि उसे यह प्लेज कराने का कहा गया कि जब तक वह 24 फीट लंबे 6 ट्रकों से सारे पैकेज नहीं उतार लेगा, तब तक वह पानी का ब्रेक नहीं लेगा और न ही शौचालय जाएगा।

टीवी चैनल पर रिपोर्ट में हुआ था खुलासा

एक टीवी चैनल पर भी 16 मई को एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के गोदाम की इनबाउंड टीम ने 8 बार शपथ ली थी। गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी इसकी पुष्टि की थी। रिपोर्ट के अनुसार गोदाम से निकलने वाले सामानों की हैंडलिंग करने वाली आउटबाउंड टीम के लिए टारगेट पूरे करना जरूरी था। टीम को रोजाना उसके टार्गेट की याद दिलाई जाती थी। हरियाणा के मानेसर गोदाम की एक महिला कर्मचारी के हवाले से भी कहा गया था कि कार्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं थी।

मानवाधिकार आयोग ने बताया श्रम कानूनों का उल्लंघन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन रिपोर्ट्स पर स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए ही केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अमेजन इंडिया और उसके आसपास के पांच गोदाम कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को लगातार कई घंटों तक काम करने का दबाव बनाया जा रहा है।

Amazon ने क्या कहा रिपोर्ट्स पर

इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केन्द्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उन्हें सुरक्षित तथा कम्फर्टेबल वर्किंग एनवायर्नमेंट सुनिश्चित करने के लिए डिजाईन किया गया है। कार्यालयों में एंप्लाई और एसोशिएट्स अपनी वर्किंग ड्यूटी के

दौरान पानी पीने तथा शौचालय जाने के लिए अनौपचारिक ब्रेक ले सकते हैं या किसी मैनेजर/ एचआर से भी बात कर सकते हैं।

Amazon India under human rights commission lens for alleged 'anti-labour practices' in Manesar warehouses

https://www.msn.com/en-in/money/topstories/amazon-india-under-human-rights-commission-lens-for-alleged-anti-labour-practices-in-manesar-warehouses/ar-BB1oxUil

Amazon has come under the lens of the National Human Rights Commission (NHRC) for alleged “anti-labour practices”. The commission has issued a notice to the Centre over a report alleging such practices at one of the warehouses in Manesar.

The NHRC took suo motu cognisance of a media report that stated that at one of Amazon India’s warehouses "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended". The commission stated that if the contents of the report are true then this tantamounts to serious human rights violation of the workers as well as violation of labour laws and guidelines by the Union Ministry of Labour and Employment

In the proceedings of the case shared by NHRC where it mentioned the name of the company as Amazon India, it said "a female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites.”

Amazon India, in its response, had earlier told Business Today, “The safety and wellbeing of our employees and associates is our top priority. We’re confident the infrastructure and facilities at our fulfilment centres are industry leading, designed to ensure a safe and comfortable working environment for our employees and associates.”

The spokesperson said that the buildings have heat index monitoring devices and the company constantly monitors changes in temperature, especially during the summer months. If the heat or humidity inside the buildings increase, then they take action to provide comfortable working conditions, including temporarily suspending work. “We have cooling measures in all our buildings, including ventilation systems, fans, and spot coolers," the spokesperson added

The NHRC highlighted that five warehouses in and around Manesar are accused of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

The NHRC has issued a notice to the Secretary of Union Ministry of Labour and Employment, and has sought a detailed report within a week. The commission highlighted that even if the workers work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they would not be able to unload more than four trucks a day.

Amazon asked workers not to take toilet breaks: Report

https://www.msn.com/en-in/news/India/amazon-asked-workers-not-to-take-toilet-breaks-report/ar-BB1oxtsP

NEW DELHI: Taking suo motu cognisance of a news report alleging anti-labour practices at an Amazon India warehouse in Haryana's Manesar, National Human Rights Commission has issued notice to the central govt asking for its response within a week.

The commission said the report, if true, raised a serious issue of human rights of workers in violation of labour laws and guidelines issued by the ministry of labour and employment from time to time

During the proceedings of the case, the report was cited, with workers saying they were made to pledge that they would not take toilet or water breaks until their work target was met.

According to the proceedings of the case, "At one of the warehouses of Amazon India in Haryana's Manesar, a 24-year-old worker was asked to pledge that he would not take toilet or water breaks until he finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended".

The proceedings of the case cited a report on a TV channel on May 16 which showed that in the past month, the warehouse's 'inbound team' had taken the pledge approximately eight times, especially on busy days with higher workloads, as confirmed by employees. The report said the 'outbound team', which handles items leaving the warehouse, was reminded of its targets daily.

"A female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites. Reportedly, the labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948. While labour inspectors can demand corrections, there is limited enforcement," NHRC said.

The news report said one of the workers, who puts in 10 hours a day for five days a week and earns Rs 10,088 per month, said that even if they worked continuously without break, including the 30-minute lunch and tea breaks, they could not unload more than four trucks a day. A woman worker claimed that she kept standing for nine hours daily.

An Amazon India spokesperson said, "The safety and well-being of our employees and associates is our top priority. The infrastructure and facilities at our fulfilment centres are industry leading, and are designed to ensure a safe and comfortable working environment...Employees and associates are free to take informal breaks throughout their shifts to use the restroom, get water, or talk to a manager or HR."

No Water, Toilet Breaks for Workers at Amazon Warehouse in Manesar? NHRC Takes Suo Motu Cognisance

https://www.greaterkashmir.com/latest-news/no-water-toilet-breaks-for-workers-at-amazon-warehouse-in-manesar-nhrc-takes-suo-motu-cognisance/

Amazon has faced similar accusations internationally, highlighting ongoing concerns regarding the treatment of warehouse workers

New Delhi, June 20: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo moto cognisance of a media report alleging severe violations of labour laws at Amazon's warehouse in Manesar, Haryana, as reported by Bar and Bench.

According to the report, a 24-year-old worker at the warehouse was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six 24-foot trucks after their team's 30-minute tea break ended.

The NHRC noted that the contents of the news report, if true, raise serious human rights issues, potentially violating the law and guidelines issued by the Ministry of Labour and Employment. In response, the Commission issued a notice to the Secretary of the Union Ministry of Labour and Employment, requesting a detailed report on the matter within one week.

In a press release, the Commission expressed concern over these allegations, especially given the government's pro-worker laws and policies.

A female employee reportedly stated that no restroom facilities are available at the working sites. Labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

Further, according to the report, one worker, who works ten hours a day for five days a week and earns ₹10,088 per month, stated that even without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, it is impossible to unload more than four trucks per day. A female worker also claimed that she stands for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during her shift.

Amazon has faced similar accusations internationally, highlighting ongoing concerns regarding the treatment of warehouse workers. (Bar and Bench)

NHRC notice to Centre over 'anti-labour practices' at MNC workshop in Haryana's Manesar

https://hr.economictimes.indiatimes.com/amp/news/industry/nhrc-notice-to-centre-over-anti-labour-practices-at-mnc-workshop-in-haryanas-manesar/111133262

The NHRC in a statement said that it has taken suo motu cognisance of a media report that at one of the warehouses of a multi-national company in Haryana's Manesar "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended".

The NHRC has issued a notice to the Centre over reported "anti-labour practices" at one of the warehouses of a multinational company in Haryana's Manesar, officials on Wednesday said. The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of human rights of the workers in violation of the labour laws and the guidelines issued by the Union Ministry of Labour and Employment from time to time.

The NHRC in a statement said that it has taken suo motu cognisance of a media report that at one of the warehouses of a multi-national company in Haryana's Manesar "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended".

"A female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites," it added.

Reportedly, the labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948, the rights panel said.

While labour inspectors can demand corrections, there is limited enforcement, it said.

Accordingly, the NHRC has issued a notice to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment, seeking a detailed report within one week.

Issuing the notice, the Commission has also noted that the government has been insisting on improving workers' living standard.

"Apart from ensuring proper payment of minimum wages to the workers, the government schemes have been introduced to provide social security for the

labourers, including a safe working environment, safety gear in hazardous working conditions, medical insurance and free annual health check-ups of the workers by the employers," it said.

A scheme -- 'Shramev Jayate' -- was started in 2014 targeting the country's growth and maximum benefit to the workers. Maternity Benefit Amendment Act, 2017 also came into effect to increase the paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, the statement said.

As per the news report, one of the workers, who works ten hours a day for five days a week and earns Rs 10,088 per month stated that even if they work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they cannot unload more than four trucks per day, it said.

A woman worker also claimed that she keeps standing for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during duty. Reportedly, the multinational company has also encountered similar accusations internationally, the statement said.

FINANCIAL EXPRESS, Online, 21.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

India's human rights body calls for scrutiny of Amazon warehouse labour practices

https://thefinancialexpress.com.bd/world/train-collision-in-chile-kills-at-least-2-people-injures-9-others

https://thefinancialexpress.com.bd/world/train-collision-in-chile-kills-at-least-2-people-injures-9-othersIndia's human rights commission asked the government on Wednesday to look into allegations of labour law violations at an Amazon warehouse near New Delhi over alleged harsh working conditions during a severe heatwave.

Indian media this month reported that workers in the e-commerce giant's warehouse in Manesar, near New Delhi, complained of a lack of water and toilet breaks as they were under pressure to achieve packaging targets.

The National Human Rights Commission (NHRC) in a statement said the findings "raise a serious issue of human rights of the workers" and asked the labour ministry to look into the alleged labour law violations within one week.

While the NHRC statement referred to alleged misconduct by a multinational company, the Commission confirmed to Reuters it was in reference to the Amazon warehouse near New Delhi.

Amazon in a statement said the safety and wellbeing of its associates and employees is its top priority.

"We provide adequate provision of water and hydration, as well as regularly scheduled rest breaks in a cooler environment, and we ensure additional breaks when temperatures are high," it said.

Amazon has faced criticism elsewhere over working conditions, including multiple strikes at a UK warehouse and a $5.9 million penalty over productivity quotas for its workers in the U.S. The company has denied that warehouse workers have fixed quotas.

In 2021, Amazon apologised after allegations emerged that its truck drivers sometimes had to urinate in bottles during delivery rounds.

Manesar is one of many Amazon warehouses in India, a key market where it has invested more than $6.5 billion.

The facility has 1,000 workers, said Amazon India Workers Association head Dharmendra Kumar, who told Reuters on Wednesday, “we are hoping for corrective measures to ensure workers have a decent living wage and adequate social protection.”

MSN, Online, 21.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC notice to Centre over 'anti-labour practices' at MNC workshop in Haryana's Manesar

https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-notice-to-centre-over-anti-labour-practices-at-mnc-workshop-in-haryana-s-manesar/ar-BB1ousnP

NEW DELHI: The NHRC has issued a notice to the Centre over reported "anti-labour practices" at one of the warehouses of a multinational company in Haryana's Manesar, officials on Wednesday said.

The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the news report, if true, raise a serious issue of human rights of the workers in violation of the labour laws and the guidelines issued by the Union Ministry of Labour and Employment from time to time

The NHRC in a statement said that it has taken suo motu cognisance of a media report that at one of the warehouses of a multi-national company in Haryana's Manesar "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take bathroom or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended".

"A female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites," it added.

Reportedly, the labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948, the rights panel said.

While labour inspectors can demand corrections, there is limited enforcement, it said.

Accordingly, the NHRC has issued a notice to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment, seeking a detailed report within one week.

Protect your Family todayIssuing the notice, the Commission has also noted that the government has been insisting on improving workers' living standard.

"Apart from ensuring proper payment of minimum wages to the workers, the government schemes have been introduced to provide social security for the labourers, including a safe working environment, safety gear in hazardous working conditions, medical insurance and free annual health check-ups of the workers by the employers," it said.

A scheme, 'Shramev Jayate' was started in 2014 targeting the country's growth and maximum benefit to the workers.

Maternity Benefit Amendment Act, 2017 also came into effect to increase the paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, the statement said.

As per the news report, one of the workers, who works ten hours a day for five days a week and earns Rs 10,088 per month stated that even if they work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they cannot unload more than four trucks per day, it said.

Segment Premier Leica Professional Camera System.A woman worker also claimed that she keeps standing for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during duty.

Reportedly, the multinational company has also encountered similar accusations internationally, the statement said.

Amazon India under human rights commission lens for alleged 'anti-labour practices' in Manesar warehouses

https://www.businesstoday.in/latest/corporate/story/amazon-india-under-human-rights-commission-lens-for-alleged-anti-labour-practices-in-manesar-warehouses-433977-2024-06-20

In the proceedings of the case shared by NHRC where it mentioned the name of the company as Amazon India, it said "a female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites."

Amazon has come under the lens of the National Human Rights Commission (NHRC) for alleged "anti-labour practices". The commission has issued a notice to the Centre over a report alleging such practices at one of the warehouses in Manesar.

The NHRC took suo motu cognisance of a media report that stated that at one of Amazon India's warehouses "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended". The commission stated that if the contents of the report are true then this tantamounts to serious human rights violation of the workers as well as violation of labour laws and guidelines by the Union Ministry of Labour and Employment.

In the proceedings of the case shared by NHRC where it mentioned the name of the company as Amazon India, it said "a female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites."

Amazon India, in its response, had earlier told Business Today, "The safety and wellbeing of our employees and associates is our top priority. We're confident the infrastructure and facilities at our fulfilment centres are industry leading, designed to ensure a safe and comfortable working environment for our employees and associates."

The spokesperson said that the buildings have heat index monitoring devices and the company constantly monitors changes in temperature, especially during the summer months. If the heat or humidity inside the buildings increase, then they take action to provide comfortable working conditions, including temporarily suspending work. "We have cooling measures in all our buildings, including ventilation systems, fans, and spot coolers," the spokesperson added.

The NHRC highlighted that five warehouses in and around Manesar are accused of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

The NHRC has issued a notice to the Secretary of Union Ministry of Labour and Employment, and has sought a detailed report within a week. The commission highlighted that even if the workers work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they would not be able to unload more than four trucks a day.

Human rights commission issues notice to Centre over anti-labour practices in Amazon's Manesar warehouse

https://www.editorji.com/business-news/human-rights-commission-issues-notice-to-amazon-india-over-anti-labour-practices-in-manesar-warehouse-1718859516071

NHRC has issued a notice to Centre regarding alleged anti-labour practices at Amazon India's Manesar warehouse, including denial of restroom facilities and forced work without breaks

The National Human Rights Commission has issued a notice to Centre over alleged “anti-labour practices” at Amazon India's Manesar warehouse. The commission took suo motu cognisance of a media report that stated that at one of Amazon India’s warehouses "a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended".

Notice to Centre over Amazon India

As per Business Today, the Commission stated that if the contents of the report are true then this tantamounts to serious human rights violation of the workers as well as violation of labour laws and guidelines by the Union Ministry of Labour and Employment.

In the proceedings of the case shared by NHRC, it said "a female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites.”

Meanwhile, an Amazon India spokesperson had told Business Today that the safety and well-being of the employees are its top priority.

“The safety and wellbeing of our employees and associates is our top priority. We’re confident the infrastructure and facilities at our fulfilment centres are industry leading, designed to ensure a safe and comfortable working environment for our employees and associates”, Amazon India Spokesperson told Business Today.

The Spokesperson further added that the firm has heat index monitoring devices and that the company constantly monitors changes in temperature, especially during the summer months. If the heat or humidity inside the buildings increase, then they take action to provide comfortable working conditions, including temporarily suspending work. “We have cooling measures in all our buildings, including ventilation systems, fans, and spot coolers," the spokesperson added.

The Human rights commission has however highlighted that even if the workers work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they would not be able to unload more than four trucks a day.

NHRC further highlighted that five warehouses in and around Manesar are accused of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948. The commission has also issued a notice to the Secretary of Union Ministry of Labour and Employment, and has sought a detailed report within a week.

Amazon India faces human rights commission's scrutiny over alleged anti-labor practices

https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/amazon-india-faces-nhrc-scrutiny-over-alleged-anti-labor-practices/articleshow/111129975.cms

Amazon India has come under the scrutiny of the National Human Rights Commission (NHRC) in India. The human rights commission took a suo motu cognisance and has sent a notice to the Centre over a report alleging anti-labour practices at one of the warehouses of Amazon India in Haryana's Manesar, reports PTI.
In a statement, the NHRC observed that the contents of the news report, if true, raises a serious issue of human rights of the workers in violation of the labour laws and the guidelines issued by the Union Ministry of Labour and Employment from time to time.

Amazon worker not given toilet or water break: Report

Earlier this week, a media report pointed out that at one of Amazon's warehouses in Haryana's Manesar 'a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team's 30-minute tea break had ended'. "A female employee at the Manesar warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites," it added.

What does the NHRC statement to the union government say?

The NHRC has issued a notice to the secretary, union ministry of labour and employment, seeking a detailed report within one week. In its statement, it said that reportedly, the labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

What Amazon said?

The PTI report states that Amazon said that its employees and associates are free to take informal breaks throughout their shifts to use the restroom, get water, or talk to a manager.

"Safety and well-being of our employees and associates is our top priority. The infrastructure and facilities at our fulfillment centres are industry leading, and are designed to ensure a safe and comfortable working environment. All our buildings have heat index monitoring devices and we constantly monitor changes in temperature, especially during summer months. If we do find increasing heat or humidity inside our buildings, then our teams take action to provide comfortable working conditions, including temporarily suspending work," the firm said.

“We have cooling measures in all our buildings, including ventilation systems, fans, and spot coolers. We also provide water and other hydration options, as well as regularly scheduled rest breaks in a cooler environment, and additional breaks when temperatures are high. Employees and associates are free to take informal breaks throughout their shifts to use the restroom, get water, or talk to a manager or HR,” it added.

No water, toilet breaks for workers at Amazon warehouse in Manesar? NHRC takes suo motu cognisance

https://www.barandbench.com/news/delhi-court-grants-bail-arvind-kejriwal-excise-policy-case

As per a media report, a 24-year-old worker at the warehouse was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Wednesday took suo motu cognisance of a media report alleging violation of labour laws at Amazon's warehouse in Manesar, Haryana.

The Commission observed that the contents of the news report, if true, raise serious human rights issues in violation of the law and guidelines issued by the Ministry of Labour and Employment.

Accordingly, the Commission issued notice to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment, calling for a detailed report on the matter within one week.

The Commission in a press release expressed concerns over the reported allegations despite pro-worker laws and policies of the government.

As per a media report, a 24-year-old worker at the warehouse was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team’s 30-minute tea break had ended.

A female employee at the warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites. Reportedly, labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

Further, as per the news report, one of the workers, who works ten hours a day for five days a week and earns ₹10,088 per month stated that even if they work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they cannot unload more than four trucks per day.

A woman worker also claimed that she keeps standing for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during duty.

Amazon has also encountered similar accusations internationally.

National Human Rights Commission Probes Into Amazon's Warehouse Near Delhi Over Anti-Labour Practices

https://www.freepressjournal.in/business/national-human-rights-commission-probes-into-amazons-warehouse-near-delhi-over-anti-labour-practices

We ensure additional breaks when temperatures are high, as well as regularly scheduled rest breaks in a cooler environment and adequate provision of water and hydration.

The National Human Rights Commission (NHRC) in India is investigating Amazon India. According to reports, the human rights commission took 'Suo Moto' cognizance of a report alleging anti-labor practices at one of Amazon India's warehouses in Manesar, Haryana, and sent a notice to the Center about it.

The NHRC noted in a statement that the news report's contents raise serious concerns about workers' human rights violations of labor laws and occasionally issued guidelines by the Union Ministry of Labour and Employment.

The findings "raise a serious issue of human rights for the workers," according to a statement from the National Human Rights Commission (NHRC), which also requested that the labor ministry look into the alleged labor law violations within a week.

Amazon said in a statement that its top priority is the safety and well-being of its associates and employees.

It stated, "We ensure additional breaks when temperatures are high, as well as regularly scheduled rest breaks in a cooler environment and adequate provision of water and hydration."

Amazons's Previous Fiascos

Other places where Amazon has been criticized for working conditions include a UK warehouse where there were several strikes and a USD 5.9 million fine for exceeding productivity targets for US employees. The business disputes the existence of set quotas for warehouse employees.

Amazon issued an apology in 2021 in response to reports that some of its delivery drivers were occasionally required to urinate into bottles.

Amazon has invested over USD 6.5 billion in India, where Manesar is just one of many warehouses.

Head of the Amazon India Workers Association, Dharmendra Kumar, told Reuters on Wednesday that there are 1,000 employees at the facility and that "we are hoping for corrective measures to ensure workers have a decent living wage and adequate social protection."

GREATER KASHMIR, Online, 21.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

No Water, Toilet Breaks for Workers at Amazon Warehouse in Manesar? NHRC Takes Suo Motu Cognisance

https://www.greaterkashmir.com/latest-news/no-water-toilet-breaks-for-workers-at-amazon-warehouse-in-manesar-nhrc-takes-suo-motu-cognisance/

Amazon has faced similar accusations internationally, highlighting ongoing concerns regarding the treatment of warehouse workers

New Delhi, June 20: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo moto cognisance of a media report alleging severe violations of labour laws at Amazon's warehouse in Manesar, Haryana, as reported by Bar and Bench.

According to the report, a 24-year-old worker at the warehouse was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six 24-foot trucks after their team's 30-minute tea break ended.

The NHRC noted that the contents of the news report, if true, raise serious human rights issues, potentially violating the law and guidelines issued by the Ministry of Labour and Employment. In response, the Commission issued a notice to the Secretary of the Union Ministry of Labour and Employment, requesting a detailed report on the matter within one week.

In a press release, the Commission expressed concern over these allegations, especially given the government's pro-worker laws and policies.

A female employee reportedly stated that no restroom facilities are available at the working sites. Labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

Further, according to the report, one worker, who works ten hours a day for five days a week and earns ₹10,088 per month, stated that even without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, it is impossible to unload more than four trucks per day. A female worker also claimed that she stands for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during her shift.

Amazon has faced similar accusations internationally, highlighting ongoing concerns regarding the treatment of warehouse workers. (Bar and Bench)

'Amazon Makes Workers Pledge Not To Take Toilet Breaks?' NHRC Takes Cognisance, Seeks Report From Labour Ministry

https://news.abplive.com/business/amazon-makes-workers-pledge-not-to-take-toilet-breaks-nhrc-takes-cognisance-seeks-report-from-labour-ministry-1697081

In a recent development the National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report alleging violation of labour laws at Amazon's Manesar warehouse in state of Haryana.

In a recent development the National Human Rights Commission (NHRC) took suo motu cognisance of a media report alleging violation of labour laws at Amazon's Manesar warehouse in state of Haryana. NHRC has sought a detailed report from the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment within a week.

The NHRC has taken cognisance of the media report that alleged that at one of the warehouses of a multinational company in Haryana’s Manesar, a 24-year-old worker was asked to pledge that they would not take toilet or water breaks until they finished unloading packages from six trucks, each measuring 24 feet long, after their team’s 30-minute tea break had ended.

The notice further stated that a female employee at the Manesar warehouse reportedly alleged that no restroom facilities are available on the working sites.

"Reportedly, the labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948. While labour Inspectors can demand corrections, there is limited enforcement," the notice read.

The Commission raised serious issues of human rights of the workers in violation of the labour laws and the guidelines issued by the Union Ministry of Labour and Employment from time to time.

"Accordingly, the Commission has issued to the Secretary, Union Ministry of Labour and Employment calling for a detailed report in the matter within one week."

The NHRC also issued notice, and noted that the government has been insisting on improving workers' living standards.

A woman worker also claimed that she keeps standing for nine hours daily and is required to evaluate 60 small products or 40 medium-sized products per hour during duty.

A female employee at the warehouse reportedly stated that no restroom facilities are available on the working sites. Reportedly, labour associations in India have accused five warehouses in and around Manesar of violating regulations outlined in the Factories Act, 1948.

Further, as per the news report, one of the workers, who works ten hours a day for five days a week and earns Rs 10,088 per month stated that even if they work continuously without breaks, including the 30-minute lunch and tea breaks, they cannot unload more than four trucks per day.

Amazon has also encountered similar accusations internationally.

"Apart from ensuring proper payment of minimum wages to the workers, government schemes have been introduced to provide social security for the labourers including a safe working environment, safety gear in hazardous working conditions, medical insurance and free annual health check-ups of the workers by the employers. A scheme was started 'Shramev Jayate' in the year 2014 targeting the country's growth and maximum benefit to the workers. Maternity Benefit Amendment Act, 2017 also came into effect to increase the paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks." the NHRC notice read.

एनएचआरसी ने दो श्रमिकों की मौत पर हरियाणा को जारी किया नोटिस

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/6/20/NHRC-issues-notice-to-Haryana-over-death-of-two-workers.php

नई दिल्ली, 20 जून (हि.स.)। राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 13 जून की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के सोनीपत जिले के बाजिदपुर सबोली गांव के पास एक निजी पैकेजिंग फैक्टरी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो भाइयों की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बता या गया है कि उनका तीसरा साथी जो उसी गांव का था, इस दुर्घटना में बच गया है। पुलिस अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लि ए भेज दिया है और फैक्टरी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। घटना में फैक्टरी मालिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही स्पष्ट है, क्योंकिक्यों कथित तौर पर, सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

ऐसी घटनाएं तब हो रही हैं, जब आयोग मैन्युअल रूप से किये जाने वाले जोखिम भरे सफाई कार्य को समाप्त करने और मशीनों का उपयोग करने तथा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए 24.9.2021 को जारी अपनी परामर्शी और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को नियमित रूप से दोहराता रहा है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को नोटिस जारी कर मामले में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मामले में दर्ज एफआईआर, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा मृतक श्रमिकों के परिजनों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास की स्थिति शामिल है।

नोटिस जारी करते हुए, आयोग द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में इस बात को भी लाया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंवें जिंग या जोखिमभरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण पर आधारित परामर्शी में उल्लेख है कि जोखिम भरे सफाई कार्य करते समय किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, स्थानीय प्राधिकारी और ठेकेदार अथवा नियोक्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा, भले ही सफाई कर्मचारी की नियुक्ति व कार्य पर रखना किसी भी प्रकार से किया गया हो। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 324/2020) दिनांक 20.10.2023 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसिजें यों का यह कर्तव्य है कि वे सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करें। हिन्दुस्थान समाचार/ सुशील/रामानुज

एनएचआरसी ने दो श्रमिकों की मौत पर हरियाणा को जारी किया नोटिस

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/6/20/NHRC-issues-notice-to-Haryana-over-death-of-two-workers.php

नई दिल्ली, 20 जून (हि.स.)। राष्ट्री य मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 13 जून की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के सोनीपत जिले के बाजिदपुर सबोली गांव के पास एक निजी पैकेजिंग फैक्टरी में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो भाइयों की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बता या गया है कि उनका तीसरा साथी जो उसी गांव का था, इस दुर्घटना में बच गया है। पुलिस अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लि ए भेज दिया है और फैक्टरी मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। घटना में फैक्टरी मालिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बरती गयी लापरवाही स्पष्ट है, क्योंकिक्यों कथित तौर पर, सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। ऐसी घटनाएं तब हो रही हैं, जब आयोग मैन्युअल रूप से किये जाने वाले जोखिम भरे सफाई कार्य को समाप्त करने और मशीनों का उपयोग करने तथा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए 24.9.2021 को जारी अपनी परामर्शी और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को नियमित रूप से दोहराता रहा है। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को नोटिस जारी कर मामले में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मामले में दर्ज एफआईआर, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा मृतक श्रमिकों के परिजनों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास की स्थिति शामिल है।

नोटिस जारी करते हुए, आयोग द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में इस बात को भी लाया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंवें जिंग या जोखिमभरे सफाई कार्य में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण पर आधारित परामर्शी में उल्लेख है कि जोखिम भरे सफाई कार्य करते समय किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, स्थानीय प्राधिकारी और ठेकेदार अथवा नियोक्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा, भले ही सफाई कर्मचारी की नियुक्ति व कार्य पर रखना किसी भी प्रकार से किया गया हो। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपी (सी) संख्या 324/2020) दिनांक 20.10.2023 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसिजें यों का यह कर्तव्य है कि वे सीवर आदि की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करें।

दाहिने की जगह बाय घुटने का कर दिया ऑपरेशन एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस

https://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/operation-done-on-wrong-knee-124062000070_1.html

ला भा र्थी हो ने के बा वजूद मरी ज से शुक भी वसूला

Operation done on wrong knee : ह या णा के पा नी पत के एक अता ल में मरी ज के दा ने घुटने के न पर क त तौ र पर बा एं घुटनेका ऑपरेशन ए जा ने की खबरों पर रा य मा नवा का र आयो ग (NHRC) ने नई ली में ह या णा (Haryana) प्रदेश सरकार और रा य के पु स प्रमुख (DGP) को नो स जा री या है। आयो ग ने गुवा र को एक बया न में कहा खबर के अनुसा र अता ल ने आयुमा न-भा रत प्रधा नमंत्री जन आरो य यो जना का ला भा र्थी हो ने के बा वजूद मरी ज से शुक भी वसूला । आयो ग ने इस खबर का वत: सं न या पा नी पत के एक अता ल में एक मरी ज के चो ल दा ने घुटनेके न पर उसके बा एं घुटने का क त प से ऑपरेशन कर या गया ।

बया न के अनुसा र खबरों में यह भी कहा गया है जब प वा र के सदयों ने रो ध या तब डॉ टरों ने तका ल उसके सरे घुटने की सर्जरी की ले न अब मरी ज चल- र नहीं पा रहा है। अता ल ने उससे 8000 पए ए और उसका आयुमा न भा रत का र्ड भी ले या । आयो ग ने कहा है य खबर की षय-वतु में स ई है तो इससे सा ला परवा ही के का रण पी त के जी वन और वा य के अ कारों के उलंघन जैसे गंभी र मु उठते हैं। आयो ग ने ह या णा के मुय स व और पु स महा देशक को नो स जा री कर एक सता ह के अंदर तृत पो र्ट मां गी है। उसने इन दो नों से यह भी बता ने को कहा है अपरा यों के प्र या का र्रवा ई की गई और मरी ज को या कोई मुआवजा या गया ।

एनएचआरसी ने कहा ऐसे जी अता लों , जहां मरी जों का शो षण या जा ता है और उनके सा थ क्रूर एवं अमा नवी य वहा र या जा ता है, पर नजर रखने के अपने दा व को भा ने में फल रहने वा ले अ का री जवा बदेही से बच नहीं सकते। खबर के अनुसा र मरी ज के प वा र के सदयों की 2006 में एक र्घटना में मौ त हो गई और तब से वह मजरी कर अपनी आजी का चला रहा था । घर में सा फ-सफा ई के दौ रा न वह र गया और उसके दा ने घुटने में चो ट लग गई थी ।(भा षा)

दायें की जगह बायें घुटने का कर दिया ऑपरेशन, NHRC ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

https://navbharatlive.com/delhi/nhrc-sent-notice-to-haryana-government-and-dgp-in-wrong-knee-operation-case-927992.html

पानीपत के एक अस्पताल में मरीज के चोटिल दाहिने घुटने के स्थान पर बायें घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया। जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तब डॉक्टरों ने तत्काल उसके दूसरे घुटने की सर्जरी भी कर दी। अब मरीज चल-फिर भी नहीं पा रहा है।

नई दिल्ली : हरियाणा के पानीपत में डॉक्टरों द्वारा मरीज के इलाज में गभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक अस्पताल में मरीज के दाहिने घुटने के स्थान पर कथित तौर पर बायें घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि अस्पताल ने आयुष्मान योजना का लाभार्थी होने के बावजूद मरीज से शुल्क भी वसूला।

इस मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि खबर के अनुसार अस्पताल ने आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होने के बावजूद मरीज से शुल्क भी वसूला। आयोग ने इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया जिसमें जानकारी मिली है कि पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के चोटिल दाहिने घुटने के स्थान पर उसके बायें घुटने का कथित रूप से ऑपरेशन कर दिया गया। बयान के अनुसार खबरों में यह भी कहा गया है जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तब डॉक्टरों ने तत्काल उसके दूसरे घुटने की सर्जरी की लेकिन अब मरीज चल-फिर नहीं पा रहा है।

8000 रुपये वसूले, आयुष्मान कार्ड भी ले लिया

आरोप यह भी लगाये गये हैं कि अस्पताल ने मरीज से 8000 रुपये लिए और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी ले लिया। मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि यदि खबर की विषय-वस्तु में सच्चाई है, तो इससे चिकित्सा लापरवाही के कारण पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दे उठते हैं। इस मामले में आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मानवाधिकार आयोग ने इन दोनों से यह भी बताने को कहा है कि अपराधियों के प्रति क्या कार्रवाई की गयी और मरीज को क्या कोई मुआवजा दिया गया। एनएचआरसी ने कहा कि ऐसे निजी अस्पतालों, जहां मरीजों का शोषण किया जाता है और उनके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पर नजर रखने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रहने वाले अधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते।

मजदूरी कर जीविका चलाता है पीड़ित

मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित मरीज के परिवार के सदस्यों की 2006 में एक दुर्घटना में मौत हो गयी थी। तब से पीड़ित मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहा था। जानकारी के अनुसार घर में साफ-सफाई के दौरान वह गिर गया था जिससे उसके दाहिने घुटने में चोट लग गयी थी। चोट लगने के कारण ही वह इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती हुआ था। (एजेंसी इनपुट के साथ)

National News: मरीज के 'गलत घुटने' की सर्जरी को लेकर एनएचआरसी ने की कड़ी कार्यवाही

https://jantaserishta.com/national/nhrc-takes-strict-action-over-surgery-on-patients-wrong-knee-3337991

national news: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का कथित तौर पर ऑपरेशन किया गया।गुरुवार को जारी एक बयान में, एनएचआरसी ने पाया कि एक मीडिया Media रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद अस्पताल ने मरीज से पैसे भी वसूले।एनएचआरसी ने "पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के घायल

Injured दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का गलत तरीके से ऑपरेशन करने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है"।कथित तौर पर, जब मरीज के परिवार के सदस्यों ने विरोध किया, तो डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे घुटने की सर्जरी की, लेकिन मरीज चलने में असमर्थ है। बयान में कहा गया है कि अस्पताल ने उससे 8,000 रुपये वसूले और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी छीन लिया।आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो "पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनने वाली चिकित्सा Treatment लापरवाही" का गंभीर मुद्दा उठाती है।तदनुसार, इसने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मरीज को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।

NHRC ने पानीपत अस्पताल में घुटने की सर्जरी में हुई चूक को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया

https://jantaserishta.com/local/haryana/nhrc-issues-notice-to-haryana-government-over-lapses-in-knee-surgery-at-panipat-hospital-3338047

Haryana हरियाणा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का कथित तौर पर ऑपरेशन किया गया।गुरुवार को जारी एक बयान में, एनएचआरसी ने पाया कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद अस्पताल ने मरीज से पैसे भी वसूले।एनएचआरसी ने "पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के घायल दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का गलत तरीके से ऑपरेशन करने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है"।कथित तौर पर, जब मरीज के परिवार के सदस्यों ने विरोध किया, तो डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे घुटने की सर्जरी की, लेकिन मरीज चलने में असमर्थ था। बयान में कहा गया है कि अस्पताल ने उससे 8,000 रुपये वसूले और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी छीन लिया।

आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो "पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनने वाली चिकित्सा लापरवाही" का गंभीर मुद्दा उठाती है।तदनुसार, इसने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मरीज को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।

एनएचआरसी ने कहा, "ऐसे निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने और निगरानी रखने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जहां मरीजों का शोषण किया जा रहा है और उनके साथ क्रूरता की जा रही है और साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।"मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित ने 2006 में एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था और तब से वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। बयान में कहा गया है कि घर की सफाई करते समय गिरने से उसके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी।

चोट लगी थी दायें घुटने में, ऑपरेशन कर दिया बायें पैर का, NHRC ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

https://www.india.com/hindi-news/haryana/nhrc-issues-notice-to-haryana-govt-after-panipat-hospital-did-operation-on-wrong-knee-of-a-patient-7028175/

Haryana News: इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश सरकार और हरियाणा के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़ित को साफ-सफाई के दौरान गिरने से चोट लगी थी.

Haryana Knee Operation News: हरियाणा के पानीपत से अस्पताल की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के एक अस्पताल में मरीज के दाहिने घुटने के स्थान पर कथित तौर पर बायें घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया. इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है.

आयोग ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि खबर के अनुसार अस्पताल ने आयुष्मान-भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होने के बावजूद मरीज से शुल्क भी वसूला. आयोग ने इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया कि पानीपत के अस्पताल में एक मरीज के चोटिल दाहिने घुटने के स्थान पर उसके बायें घुटने का कथित रूप से ऑपरेशन कर दिया गया.

अस्पताल ने पैसों के साथ आयुष्मान कार्ड भी लिया

बयान के अनुसार खबरों में यह भी कहा गया है जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तब डॉक्टरों ने तत्काल उसके दूसरे घुटने की सर्जरी की लेकिन अब मरीज चल-फिर नहीं पा रहा है. अस्पताल ने उससे 8000 रुपये लिए और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी ले लिया.

आयोग ने कहा है कि यदि खबर की विषय-वस्तु में सच्चाई है, तो इससे चिकित्सा लापरवाही के कारण पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन जैसे गंभीर मुद्दे उठते हैं.

आयोग ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उसने इन दोनों से यह भी बताने को कहा है कि अपराधियों के प्रति क्या कार्रवाई की गयी और मरीज को क्या कोई मुआवजा दिया गया.

'अधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते'

एनएचआरसी ने कहा, 'ऐसे निजी अस्पतालों, जहां मरीजों का शोषण किया जाता है और उनके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पर नजर रखने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रहने वाले अधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते.'

साफ-सफाई के दौरान गिरने से लगी थी चोट

खबर के अनुसार मरीज के परिवार के सदस्यों की 2006 में एक दुर्घटना में मौत हो गयी और तब से वह मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहा था. घर में साफ-सफाई के दौरान वह गिर गया और उसके दाहिने घुटने में चोट लग गयी थी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां उसके साथ ऑपरेशन के दौरान ये लापरवाही की गई.

NHRC ने पानीपत अस्पताल में घुटने की सर्जरी में हुई चूक को लेकर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया

https://jantaserishta.com/local/haryana/nhrc-issues-notice-to-haryana-government-over-lapses-in-knee-surgery-at-panipat-hospital-3338047

Haryana हरियाणा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को उन रिपोर्टों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का कथित तौर पर ऑपरेशन किया गया।गुरुवार को जारी एक बयान में, एनएचआरसी ने पाया कि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का लाभार्थी होने के बावजूद अस्पताल ने मरीज से पैसे भी वसूले।एनएचआरसी ने "पानीपत के एक अस्पताल में एक मरीज के घायल दाहिने घुटने की बजाय उसके बाएं घुटने का गलत तरीके से ऑपरेशन करने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है"।कथित तौर पर, जब मरीज के परिवार के सदस्यों ने विरोध किया, तो डॉक्टरों ने तुरंत दूसरे घुटने की सर्जरी की, लेकिन मरीज चलने में असमर्थ था। बयान में कहा गया है कि अस्पताल ने उससे 8,000 रुपये वसूले और उसका आयुष्मान भारत कार्ड भी छीन लिया।

आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो "पीड़ित के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बनने वाली चिकित्सा लापरवाही" का गंभीर मुद्दा उठाती है।तदनुसार, इसने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और मरीज को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।

एनएचआरसी ने कहा, "ऐसे निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने और निगरानी रखने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, जहां मरीजों का शोषण किया जा रहा है और उनके साथ क्रूरता की जा रही है और साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।"मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित ने 2006 में एक दुर्घटना में अपने परिवार को खो दिया था और तब से वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहा है। बयान में कहा गया है कि घर की सफाई करते समय गिरने से उसके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी।

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो भाइयों की मौत पर NHRC ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा

https://www.prabhasakshi.com/national/nhrc-sends-notice-to-haryana-government-on-death-of-two-brothers-while-cleaning-septic-tank

बयान में कहा गया है, ‘‘इस रिपोर्ट में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा अधिकारियों द्वारा मृत श्रमिकों के परिजनों को प्रदान की गई राहत एवं पुनर्वास की जानकारी शामिल हो।’’

हरियाणा के सोनीपत जिले में निजी पैकेजिंग कारखाने में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण दो भाइयों की कथित तौर पर हुयी मौत से संबंधित खबरों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार और प्रदेश के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेज कर एक सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘इस रिपोर्ट में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा अधिकारियों द्वारा मृत श्रमिकों के परिजनों को प्रदान की गई राहत एवं पुनर्वास की जानकारी शामिल हो।’’

आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय कथित तौर पर श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इससे यह साफ है कि इसमें कारखाना मालिक और स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही है।

एनएचआरसी ने 13 जून 2024 को मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा के सोनीपत जिले के बाजिदपुर सबोली गांव के पास एक निजी पैकजिंग कारखाने की सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस में सांस लेने से दो भाईयों की मौत हो गई।बयान में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कारखाने के मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

NHRC Issues Notice To Haryana Govt Over Wrong Knee Surgery Incident In Panipat Hospital

https://www.newsonair.gov.in/nhrc-issues-notice-to-haryana-govt-over-wrong-knee-surgery-incident-in-panipat-hospital/

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana government over the reported surgery of a patient on the wrong knee at a hospital in Panipat. Taking suo-moto cognizance of a media report, the NHRC has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Director General of Police for a detailed report within one week. It added that the report should include the action taken against the guilty and any potential compensation provided to the patient.

The Commission said that according to the media report, instead of the victim's injured right knee, the operation was mistakenly conducted on his left knee. The media reports also claimed that the patient was charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman – Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

NHRC Flags Medical Negligence: Botched Surgery in Panipat Leads to Uproar

https://www.devdiscourse.com/article/health/2988932-blistering-heatwave-devastates-india-over-110-dead-and-thousands-suffering

The National Human Rights Commission (NHRC) has raised serious concerns after a patient in Panipat was operated on the wrong knee. Despite being a beneficiary of the Ayushman Bharat scheme, the patient was charged Rs 8,000. The NHRC has demanded a detailed report from Haryana officials within a week.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana government and the state's police chief after reports emerged of a grave medical error at a Panipat hospital, where a patient was operated on the wrong knee.

According to a media report, instead of operating the right knee, the surgeons operated on the left knee. The patient, who is a beneficiary of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), was charged Rs 8,000 for the procedure. Following protests from the patient's family, the correct knee was operated upon, but the patient remains unable to walk.

The NHRC's statement condemns the incident, highlighting it as a case of medical negligence and a violation of the patient's rights to life and health. The commission has demanded a detailed report from the Haryana chief secretary and the director general of police within one week, outlining actions taken against those responsible and any compensation provided to the patient. The NHRC emphasized that authorities cannot escape liability for failing to supervise such private hospitals.

TIMES OF INDIA, Online, 21.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notices to Haryana government, DGP over wrong knee surgery allegations

https://timesofindia.indiatimes.com/city/amritsar/nhrc-issues-notices-to-haryana-government-dgp-over-wrong-knee-surgery-allegations/articleshow/111133023.cms

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Haryana government and its police chief following allegations that a patient was operated on the wrong knee at a hospital in Panipat. This incident, reported by the media, involved the patient being charged despite being a beneficiary of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

The NHRC stated that it has taken "suo motu cognisance of a media report that a patient was wrongly operated upon his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat." In response to the family's protests, doctors then operated on the correct knee, yet the patient remains unable to walk. Additionally, the hospital charged the patient Rs 8,000 and confiscated his Ayushman Bharat card.

The Commission commented that if the reports are accurate, they highlight significant concerns regarding "medical negligence causing violation of the rights to life and health of the victim." Thus, NHRC has requested a detailed report from the Haryana government and the state's police chief within one week.

"The authorities who have failed to do their duty to supervise and keep vigil on such private hospitals cannot escape their liability, where the patients are being exploited and subjected to cruelty as well as being treated in an inhuman manner," the NHRC remarked in its statement.

The media report further outlined the patient's difficult circumstances. He lost his family in a 2006 accident and has since been working as a laborer. His right knee injury occurred when he fell while cleaning his house.
The NHRC has emphasized the need for a thorough investigation, including details on actions taken against those responsible and any compensation provided to the patient.

NHRC notice to Haryana government, DGP over surgery in patient's 'wrong knee'

https://www.thehindu.com/news/national/haryana/nhrc-notice-to-haryana-government-dgp-over-surgery-in-patients-wrong-knee/article68311130.ece

The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that a patient was wrongly operated upon his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat".

In a statement issued on June 20, the NHRC observed that according to a media report, the patient was also charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman-Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. | Photo Credit: The Hindu

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana government and the State's Director-General of Police (DGP) over reports that a patient was allegedly operated on his left knee, instead of the right at a hospital in Panipat.

In a statement issued on June 20, the NHRC observed that according to a media report, the patient was also charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman-Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report that a patient was wrongly operated upon his left knee, instead of the injured right knee at a hospital in Panipat".

Reportedly, when the family members of the patient protested, the doctors immediately conducted surgery on the other knee but the patient is unable to walk. “The hospital charged a sum of ₹8,000 from him and also took away his Ayushman Bharat card,” the statement said.

The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises serious issues of "medical negligence causing violation of the rights to life and health of the victim".

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police of Haryana, seeking detailed report within one week. “It should include details about the action taken against the guilty, and compensation, if any, provided to the patient,” it said.

The NHRC said, “The authorities who have failed to do their duty to supervise and keep vigil on such private hospitals cannot escape their liability, where the patients are being exploited and subjected to cruelty as well as being treated in an inhuman manner.” According to the media report, the victim had lost his family in an accident in 2006, and since then, he has been earning his livelihood by working as a labourer.

“His right knee had been injured when he fell while cleaning his house,” the statement said.

NHRC issues notices to Haryana govt over wrong knee surgery of labourer at private hospital in Panipat

https://thenorthlines.com/nhrc-issues-notices-to-haryana-govt-over-wrong-knee-surgery-of-labourer-at-private-hospital-in-panipat

The National Human Rights Commission has taken cognizance of a case of alleged medical negligence from Haryana which has seriously impacted a patient. As per reports, a man was mistakenly operated on his left knee instead of the right one at a private hospital in Haryana's Panipat.

It has been learnt that the patient, who had suffered an injury in his right knee, visited the hospital for the intended surgery. However, due to what is suspected to be an error, the surgery was performed on his left knee. When confronted, the hospital staff hastily conducted the operation on the other knee as well but to no benefit. The man is now unable to walk properly due to the botched up procedures.

What's worse is that the hospital allegedly charged him Rs.8,000 despite him being covered under the state-run health insurance scheme, Ayushman Bharat, and also took away his policy card. Seeing the circumstances of the case, NHRC has sent notices to the Chief Secretary and Director General of Police in Haryana seeking time-bound reports on the matter within a week. This should include detailed information about action taken against those responsible and compensation provided to the victim.

It has been pointed out that such negligent acts on part of private healthcare institutions are a violation of patients' fundamental right to life and proper medical care. Authorities cannot absolve themselves of liability where people's wellbeing and trust in the system are disregarded. The notices are hoped to brinpg justice and relief for the affected person while acting as a deterrent against future lapses as well.

NHRC Issues Notice To Haryana Govt Over Wrong Knee Surgery Incident In Panipat Hospital

https://www.jaisalmernews.com/news/state/nhrc-issues-notice-to-haryana-govt-over-wrong-knee-surgery-incident-in-panipat-hospital-245177/

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana government over the reported surgery of a patient on the wrong knee at a hospital in Panipat. Taking suo-moto cognizance of a media report, the NHRC has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Director General of Police for a detailed report within one week. It added that the report should include the action taken against the guilty and any potential compensation provided to the patient.

The Commission said that according to the media report, instead of the victim's injured right knee, the operation was mistakenly conducted on his left knee. The media reports also claimed that the patient was charged by the hospital despite being a beneficiary of Ayushman – Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

National Human Rights Commission of India to take action against Amazon for "grueling working conditions"

https://www.medianama.com/2024/06/223-national-human-rights-commission-of-india-to-take-action-against-amazon-for-grueling-working-conditions/

The National Human Rights Commission of India (NHRC) is taking action against Amazon after news reports emerged on workers criticising "grueling working conditions that could violate their human rights" The Commission said that it was taking Suo moto cognizance of anti-labour practices at one of Amazon's warehouses in Manesar, Haryana. It has issued a notice to the Secretary of Union Ministry of Labour and Employment calling for a report in one week.

Amazon India Workers Association (AIWA) wrote a letter to the Ministry of Labour and Employment, as per a press release on May 28, 2024 demanding that the government acknowledge the severe temperatures in northern and western India as a "disaster" and compensate workers accordingly for working in such conditions. They demanded a heat surcharge and access to shade, drinking water and toilets to tackle the ongoing heatwave.

Workers detail the work conditions at Amazon

The AIWA letter detailed the grueling conditioned the workers had to work under. Two workers, under pseudonyms Ravish and Pooja, detailed their experiences stating that male and female workers were forced to work under unbearable temperature in warehouses and that female workers are forced to rest in unhygienic washrooms.

One of them said, "The temperature of the warehouse is not maintained adequately. As a result, [workers] in the loading and unloading section are forced to work under unbearable temperatures… on May 28, 2024… a temperature of 31 degree Celsius (87.7 F) [was recorded] in the dock area of Amazon warehouse. In the canteen on the same day… a temperature of 32 degree Celsius (89.6 F) [was recorded]. In the stow section… the temperature recorded on that day was 34.2 degree Celsius (93.56 F) [was recorded],"

Another worker claimed that managers berated them for their poor performance and made to take oaths on target completion on 16 May, 2024. At one point, the manager even instructed the workers to swear off water or nature breaks until they reached their targets.

Noting these, the NHRC said that these conditions "raise a serious issue of human rights of the workers in violation of the labour laws and the guidelines issued by the Union Ministry of Labour and Employment from time to time." Rajendra Acharya, Regional Secretary of UNI Global Union in Asia & Pacific, said, "this situation underscores the urgent need for comprehensive labour protections and the enforcement of existing laws to safeguard workers from extreme heat."

Kamal Kumar Niyogi, Legal Advisor to AIWA, referenced the Factories Act, 1948, stating that employers are required to provide adequate seating for workers who must stand for long periods.

The impact of climate change

The NHRC has also noted the impact of climate change and subsequent heatwaves on workers. They said, “Scientists have warned that without significant global efforts to mitigate climate change, extreme weather events, including heatwaves, will become more common and severe. This trend underscores the urgent need for both immediate act .”

AIWA Convener Dharmendra Kumar also called for the disaster authorities to declare this a heatwave as a disaster and take immediate and long-term measures to protect workers’ health and livelihoods.”

Amazon’s history of poor labour conditions

The NHRC has also noted that Amazon has has faced similar scrutiny regarding labour conditions in other countries. In the US, the company has been criticized for its high injury rates and inadequate response to worker safety concerns. In Europe, Amazon has been fined and investigated for poor working conditions and union-busting activities.

Thus, the NHRC stated that “these global issues highlight a pattern of neglecting worker welfare that extends beyond India.”

Nitesh Kumar Das, an AIWA member, told MediaNama that workers have sent 15 complaints to the company regarding card-blocking, sudden removal from work and the state of working conditions inside warehouses. However, the company has not responded to any of their grievances yet.

“Most Indian companies follow India’s labour laws but Amazon does not. We want to have a tripartite dialogue with Amazon and the Indian government to ask for humane working conditions,” said Das.

Tragedy in Sonipat: NHRC Takes Action Over Septic Tank Deaths

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2989325-tragedy-in-sonipat-nhrc-takes-action-over-septic-tank-deaths

The NHRC has issued notices to the Haryana government and police chief following the death of two brothers due to poisonous gas inhalation while cleaning a septic tank at a Sonipat factory. The factory owner and local authorities are blamed for negligence and lack of safety gear.

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Haryana government and the state's police chief in response to reports of two brothers' tragic deaths from inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a packaging factory in Sonipat district.

The NHRC has emphasized the apparent 'negligence' of the factory owner and local authorities, citing that the workers were 'not provided any safety gear' during the hazardous task. The Commission's statement highlights that it had previously advised the implementation of safety protocols.

According to a media report dated June 13, 2024, the incident occurred near Bazidpur Saboli village. The third member of the group survived. The deceased were sent for a post-mortem, and an FIR has been registered against the factory owner. NHRC asserts that the news report suggests a serious violation of human rights.

ODISHA BHASKAR, Online, 21.6.2024
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC Issues Notice to Haryana Govt Over Wrong Knee Surgery Incident in Panipat

https://odishabhaskar.in/national/nhrc-notice-haryana-wrong-knee-surgery-panipat-83961/

Panipat: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Haryana government and the state's police chief following reports of a patient allegedly undergoing surgery on the wrong knee at a hospital in Panipat.

According to a media report, the patient was billed despite being a beneficiary of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY).

In a statement released on Thursday, the NHRC took *suo motu* cognizance of the report, noting that the patient was mistakenly operated on the left knee instead of the injured right knee. When the patient's family protested, the hospital performed surgery on the correct knee; however, the patient is now unable to walk. The hospital charged him Rs 8,000 and confiscated his Ayushman Bharat card.

The NHRC expressed concern over the incident, stating that it raises serious issues of medical negligence and violation of the patient's right to life and health. Notices have been sent to the Chief Secretary and Director General of Police of Haryana, demanding a detailed report within one week. The report should include actions taken against those responsible and any compensation provided to the patient.

The Commission criticized the authorities for failing to supervise private hospitals adequately, resulting in patient exploitation and inhumane treatment. The patient, who lost his family in a 2006 accident, has been earning his livelihood as a labourer. His right knee injury occurred from a fall while cleaning his house.

NHRC notice to Haryana govt DGP over death of two brothers cleaning septic tank

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2024/06/20/des18-nhrc-hr-workers.html

New Delhi, Jun 20 (PTI) The NHRC has sent notices to the Haryana government and the state's police chief over reports that two brothers died allegedly after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory in Sonipat district.

The "negligence" of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were "not provided any safety gear" while cleaning the septic tank, the National Human Rights Commission said in a statement.

The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report, carried on June 13, 2024, that two brothers died after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory near the village Bazidpur Saboli in the district Sonipat, Haryana".

Their third companion from the same village has reportedly survived the accident, it said.

The police authorities have sent the bodies of the deceased for post-mortem examination and an FIR has been registered against the factory owner, the statement said.

The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of violation of human rights.

"The negligence of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were not provided any safety gear while cleaning the septic tank.

"This even though the Commission has been reiterating the implementation of its advisory dated 24.9.2021 and guidelines of the apex court to end manual hazardous cleaning by using machines and providing safety equipment to the workers," the statement said.

Accordingly, the Commission has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Haryana, seeking a detailed report in one week including the status of the FIR registered, action taken against persons responsible as well as relief and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased workers by the authorities, it said.

Issuing the notices, the Commission has drawn the attention of the authorities concerned in its advisory on the Protection of Human Rights of the Person Engaged in Manual Scavenging or Hazardous Cleaning.

It is mentioned that in case of the death of any sanitary worker, while undertaking hazardous cleaning work, the local authority and the contractor or employer are to be

held responsible and accountable, jointly and severally, irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary worker, the statement said.

"Apart from this, the decision is given by the Supreme Court, Dr. Balram Singh vs Union of India (WP(C) No. 324 of 2020) dated 20.10.2023, provides the specific mandate that it is the duty of the local authorities and other agencies to use modern technology to clean sewers," it added.

India News | Haryana: NHRC Takes Suo Motu Cognizance on Reported Deaths of Workers While Cleaning Septic Tanks

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-haryana-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-on-reported-deaths-of-workers-while-cleaning-septic-tanks-6052997.html

Get latest articles and stories on India at LatestLY. After the death of two brothers in Haryana's Sonipat after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the case and issued notices to Haryana's Chief Secretary and the Director General of Police.

New Delhi [India], June 20 (ANI): After the death of two brothers in Haryana's Sonipat after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank, the National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the case and issued notices to Haryana's Chief Secretary and the Director General of Police.In a press release, the NHRC informed that it has taken suo motu cognizance of a media report carried on June 13, 2024, on the death of two brothers after inhaling poisonous gas while cleaning a septic tank at a private packaging factory near the village Bazidpur Saboli in Sonipat district.

Their third companion from the same village has reportedly survived the accident. The police authorities have sent the bodies of the deceased for post-mortem examination and an FIR has been registered against the factory owner.The Commission in its press release said that it has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

"The negligence of the factory owner and the local authorities is apparent, as reportedly, the workers were not provided any safety gear while cleaning the septic tank. This even though the Commission has been reiterating the implementation of its advisory dated 24.9.2021 and guidelines of the Apex court to end manual hazardous cleaning by using machines and providing safety equipment to the workers," the NHRC press release said.It further added, "Accordingly, the Commission has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Haryana calling for a detailed report in the matter within one week including the status of the FIR registered in the matter, action taken against the responsible persons as well as relief and rehabilitation provided to the next of kin of the deceased workers by the authorities."Issuing the notices, the Commission has also drawn the attention of the concerned authorities that in its advisory on the Protection of Human Rights of the Person Engaged in Manual Scavenging or Hazardous Cleaning, it is mentioned that in case of death of any sanitary worker while undertaking hazardous cleaning work, the local authority and the contractor/employer are to be held responsible and accountable, jointly and severally, irrespective of the type of hiring/engagement of the sanitary worker.

It added further, "Apart from this, the decision given by the Supreme Court, Dr Balram Singh vs Union of India (WP(C) No. 324 of 2020) dated October 20, 2023, provides the specific mandate that it is the duty of the local authorities and other agencies to use modern technology to clean sewers, etc." (ANI)

6 साल से मासूम को है दिल के ऑपरेशन का इंतजार, NHRC का दिल्ली एम्स को नोटिस, जानिए क्या कहा

https://www.msn.com/hi-in/news/India/6-%E0%A4%B8-%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%AE-%E0%A4%95-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%91%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%A8-%E0%A4%95-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%9C-%E0%A4%B0-nhrc-%E0%A4%95-%E0%A4%A6-%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%95-%E0%A4%A8-%E0%A4%9F-%E0%A4%B8-%E0%A4%9C-%E0%A4%A8-%E0%A4%8F-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B9/ar-BB1oyLde

नई दिल्ली: एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने 6 साल के बच्चे के हार्ट सर्जरी में देरी पर दिल्ली एम्स को नोटिस भेजा है। बच्चे को 2019 से ही दिल की बीमारी है और तब से उसके माता-पिता एम्स के चक्कर काट रहे हैं। हर बार उन्हें सर्जरी की तारीख दी जाती है लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। एनएचआरसी ने इस मामले को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सहयोगी अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने एम्स को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में 6 साल के एक बच्चे के दिल के ऑपरेशन में लगभग छह साल की अभूतपूर्व देरी का मामला सामने आया था।

बेगूसराय के मासूम की सर्जरी कब

बिहार के बेगूसराय का रहने वाला यह बच्चा 2019 में महज तीन महीने का था जब उसे दिल की बीमारी का पता चला था। बच्चे के माता-पिता का कहना है कि जब से उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला है, तब से लेकर अब तक वो कई बार एम्स का चक्कर लगा चुके हैं। हर बार उन्हें डॉक्टरों ने सर्जरी की नई तारीख दे दी, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। एनएचआरसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है, अगर वह सच है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। एम्स एक प्रतिष्ठित सरकारी हेल्थ संस्थान है, जहां देश भर से लोग अपने प्रियजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं।

एनएचआरसी का एम्स से सवाल

आयोग ने माना कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन यह जानकर दुख होता है कि बिहार का एक मासूम बच्चा गंभीर हालात के बावजूद छह साल से दिल की सर्जरी का इंतजार कर रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है। एनएचआरसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और एम्स के निदेशक को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में बच्चे की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और एम्स के डॉक्टरों की ओर से बताई गई सर्जरी की निर्धारित तारीख का ब्योरा भी मांगा है।

एनएचआरसी नोटिस में क्या कहा जानिए

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनएचआरसी के नोटिस में कहा गया है कि बच्चे के पिता की मासिक आय 8,000 रुपये है। इलाज के खर्च के कारण उन पर काफी आर्थिक बोझ है। दिल्ली आने-जाने और रहने-खाने में हर बार उन्हें 13,000 से 15,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। बच्चे की हालत ऐसी है कि वह बिना सांस फूले 15 कदम भी नहीं चल पाता। बीमारी की वजह से उसका शारीरिक विकास भी रुक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स की तरफ से सर्जरी में देरी के अलग-अलग कारण बताए गए हैं, जिनमें बेड उपलब्ध न होना और डॉक्टरों की अनुपस्थिति शामिल है।

एम्स ने पूरे मामले में कही ये बात

इस बीच, एम्स ने भी इन आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। एम्स मीडिया सेल की इंचार्ज प्रोफेसर रीमा दादा ने दावा किया कि इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार कर निदेशक कार्यालय को सौंप दी गई है। हालांकि, संपर्क के वक्त रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में क्या है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। उधर, बच्चे के पिता अंकित कुमार ने बताया कि एम्स के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और अगली बार दिल्ली आने पर ओपीडी में आने को कहा है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में अंकित कुमार ने बताया कि उन्होंने रोटरी पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के संस्थापक डॉ. निश्चल से भी बात की है। डॉ. निश्चल ने अंकित कुमार को बताया है कि वह बच्चे की जांच के बाद ही उसके इलाज के बारे में कोई फैसला लेंगे। अंकित कुमार 27 जून को अपने बच्चे का इलाज कराने दिल्ली आने वाले हैं।

'6 साल से बच्चे की क्यों नहीं हुई सर्जरी...?' NHRC ने दिल्ली एम्स से पूछा सवाल, 3 महीने का था तब से चल रहा इलाज

https://hindi.news18.com/news/bihar/nhrc-asked-question-from-delhi-aiims-after-case-came-of-child-who-suffer-from-heart-disease-and-not-get-surgery-8423195.html

बेगूसरायः बार-बार ऑपरेशन की डेट मिलने के बावजूद भी जब 6 साल के बच्चे के दिल का ऑपरेशन नहीं हुआ तो राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली एम्स से सवाल किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले 6 साल के बच्चे को 2019 से हार्ट की सर्जरी का इंतजार है. क्योंकि जब वह केवल तीन महीने का था तभी से एम्स नई दिल्ली में उसके हार्ट का इलाज शुरू हुआ था. लेकिन इन 6 साल में तीन बार सर्जरी की डेट मिली. लेकिन सर्जरी नहीं हुई.

वहीं जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई तो राष्ट्रीय मानवाधिकारी ने इसे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का गंभीर मामला माना है. आयोग ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है. एम्स प्रतिष्ठित और प्रमुख सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में से एक है, जहां देश भर के लोग इलाज की उम्मीद से आते हैं. लेकिन यह दर्दनाक स्थिति है कि बिहार का बच्चा अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद पिछले 6 साल से हार्ट की सर्जरी का इंतजार कर रहा है. यह वाकई चिंता का विषय है.'

NHRC ने इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और एम्स के निदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति सहित रिपोर्ट मांगी है. साथ ही एम्स नई दिल्ली पर लगे इन आरोपों को लेकर कमिटी का भी गठन कर दिया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी.

6 साल से मासूम को है दिल के ऑपरेशन का इंतजार, NHRC का दिल्ली एम्स को नोटिस, जानिए क्या कहा

https://navbharattimes.indiatimes.com/india/nhrc-takes-note-of-6-year-wait-for-cardiac-surgery-at-aiims/articleshow/111134424.cms#google_vignette

नई दिल्ली: एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग ने 6 साल के बच्चे के हार्ट सर्जरी में देरी पर दिल्ली एम्स को नोटिस भेजा है। बच्चे को 2019 से ही दिल की बीमारी है और तब से उसके माता-पिता एम्स के चक्कर काट रहे हैं। हर बार उन्हें सर्जरी की तारीख दी जाती है लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। एनएचआरसी ने इस मामले को मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सहयोगी अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने एम्स को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट में 6 साल के एक बच्चे के दिल के ऑपरेशन में लगभग छह साल की अभूतपूर्व देरी का मामला सामने आया था।

बेगूसराय के मासूम की सर्जरी कब

बिहार के बेगूसराय का रहने वाला यह बच्चा 2019 में महज तीन महीने का था जब उसे दिल की बीमारी का पता चला था। बच्चे के माता-पिता का कहना है कि जब से उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला है, तब से लेकर अब तक वो कई बार एम्स का चक्कर लगा चुके हैं। हर बार उन्हें डॉक्टरों ने सर्जरी की नई तारीख दे दी, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। एनएचआरसी ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया है, अगर वह सच है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं हर व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। एम्स एक प्रतिष्ठित सरकारी हेल्थ संस्थान है, जहां देश भर से लोग अपने प्रियजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं।

एनएचआरसी का एम्स से सवाल

आयोग ने माना कि देश भर के सरकारी अस्पतालों में कई तरह की बाधाएं हैं, लेकिन यह जानकर दुख होता है कि बिहार का एक मासूम बच्चा गंभीर हालात के बावजूद छह साल से दिल की सर्जरी का इंतजार कर रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है। एनएचआरसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और एम्स के निदेशक को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के अंदर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में बच्चे की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और एम्स के डॉक्टरों की ओर से बताई गई सर्जरी की निर्धारित तारीख का ब्योरा भी मांगा है।

एनएचआरसी नोटिस में क्या कहा जानिए

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनएचआरसी के नोटिस में कहा गया है कि बच्चे के पिता की मासिक आय 8,000 रुपये है। इलाज के खर्च के कारण उन पर काफी आर्थिक बोझ है। दिल्ली आने-जाने और रहने-खाने में हर बार उन्हें 13,000 से 15,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। बच्चे की हालत ऐसी है कि वह बिना सांस फूले 15 कदम भी नहीं चल पाता। बीमारी की वजह से उसका शारीरिक विकास भी रुक गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स की तरफ से सर्जरी में देरी के अलग-अलग कारण बताए गए हैं, जिनमें बेड उपलब्ध न होना और डॉक्टरों की अनुपस्थिति शामिल है।

एम्स ने पूरे मामले में कही ये बात

इस बीच, एम्स ने भी इन आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। एम्स मीडिया सेल की इंचार्ज प्रोफेसर रीमा दादा ने दावा किया कि इस मामले में एक रिपोर्ट तैयार कर निदेशक कार्यालय को सौंप दी गई है। हालांकि, संपर्क के वक्त रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में क्या है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। उधर, बच्चे के पिता अंकित कुमार ने बताया कि एम्स के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और अगली बार दिल्ली आने पर ओपीडी में आने को कहा है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से बातचीत में अंकित कुमार ने बताया कि उन्होंने रोटरी पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम के संस्थापक डॉ. निश्चल से भी बात की है। डॉ. निश्चल ने अंकित कुमार को बताया है कि वह बच्चे की जांच के बाद ही उसके इलाज के बारे में कोई फैसला लेंगे। अंकित कुमार 27 जून को अपने बच्चे का इलाज कराने दिल्ली आने वाले हैं।

Long delay in cardiac issue-related surgery of a boy: NHRC notice to Health Min, AIIMS-Delhi over

https://www.thehansindia.com/hans/opinion/news-analysis/how-hindus-nos-declined-in-kashmir-879494?infinitescroll=1

New Delhi: The NHRC has issued notices to the Union Health Ministry and the AIIMS-Delhi chief over reports alleging that a six-year-old boy from Bihar has been waiting for a cardiac issue-related surgery since 2019 when he was just three months old, officials said on Wednesday.Reportedly, the reasons provided by the AIIMS here have varied, “ranging from unavailability of beds to the doctor’s absence”. The institute has also constituted a committee to verify the allegations, the National Human Rights Commission (NHRC) said in a statement.

The rights panel said it has taken suo motu cognisance of a media report, carried on June 13, that a six-year-old boy from Begusarai has been waiting for a cardiac issue-relate surgery since 2019 when he was three months old. Doctors at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi have only been “providing dates” for the surgery on every visit by his family, the statement said.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a very serious issue of violation of human rights. “The right to health and medical care is a basic human right.The AIIMS is one of the prestigious and premier public-funded healthcare institutions where a large number of people visit daily from across the country in the hope of getting their loved ones treated for their ailments by the best doctors of the nation,” the statement said. The NHRC said it is aware of the “constraints faced by public hospitals” across the country but it is still “painful to know that the young boy from Bihar has been waiting for cardiac surgery for about the last six years despite his poor health condition. This is indeed a matter of deep concern.”

6 year old innocent is waiting for heart operation, NHRC issues notice to Delhi AIIMS, know what was said

https://presswire18.com/6-year-old-innocent-is-waiting-for-heart-operation-nhrc-issues-notice-to-delhi-aiims-know-what-was-said/

New Delhi: NHRC i.e. National Human Rights Commission has sent a notice to Delhi AIIMS over the delay in heart surgery of a 6-year-old child. The child has been suffering from heart disease since 2019 and since then his/her parents have been visiting AIIMS. Every time they are given a date for surgery but the operation does not take place. NHRC has termed this case as a violation of human rights. The National Human Rights Commission took cognizance of a report published in the sister newspaper 'Times of India'. NHRC has issued a notice to AIIMS. The report revealed an unprecedented delay of almost six years in the heart operation of a 6-year-old child.

When will the surgery of Begusarai's innocent child be done?

This child from Begusarai, Bihar was just three months old in 2019 when he/she was diagnosed with a heart disease. The child's parents say that ever since they came to know about this disease, they have visited AIIMS several times. Every time the doctors gave them a new date for surgery, but the operation could not be done. NHRC said that if whatever is said in the media report is true, then it is a case of serious violation of human rights. Health and medical facilities are the basic rights of every person. AIIMS is a prestigious government health institution, where people from all over the country come to get their loved ones treated.

NHRC's question to AIIMS

The commission acknowledged that there are many obstacles in government hospitals across the country, but it is sad to know that an innocent child from Bihar is waiting for heart surgery for six years despite serious conditions. This is a matter of great concern. NHRC has issued a notice to the Secretary of the Union Ministry of Health and Family Welfare and the Director of AIIMS and sought a detailed report in this matter within a week. The commission has also sought details of the current health condition of the child and the scheduled date of surgery given by the AIIMS doctors in the report.

Know what was said in the NHRC notice

Citing a report published in the Times of India, the NHRC notice said that the child's father's monthly income is Rs 8,000. he/she is under a huge financial burden due to the cost of treatment. he/she has to spend Rs 13,000 to Rs 15,000 every time for travelling to and from Delhi and for food and lodging. The child's condition is such that he/she cannot walk even 15 steps without getting breathless. his/her physical development has also stopped due to the disease. According to the report, AIIMS

has given various reasons for the delay in the surgery, including non-availability of beds and absence of doctors.

AIIMS said this in the whole matter

Meanwhile, AIIMS has also formed a committee to investigate these allegations. Professor Reema Dada, in-charge of AIIMS media cell, claimed that a report has been prepared in this matter and submitted to the director's office. However, at the time of contact, detailed information of the report was not available to her. She said that efforts are being made to gather information about what is in the report. On the other hand, the child's father Ankit Kumar said that AIIMS officials have contacted him/her and asked him/her to come to the OPD the next time he/she comes to Delhi. Talking to 'Times of India', Ankit Kumar said that he/she has also spoken to Dr. Nischal, founder of Rotary Pediatric Cardiac Surgery Program. Dr. Nischal has told Ankit Kumar that he/she will take a decision about the child's treatment only after examining him/her. Ankit Kumar is coming to Delhi on June 27 to get his/her child treated.

Alleged Delay Of 6 Years In Cardiac Surgery: NHRC Issues Notice To Centre, Delhi AIIMS

https://medicaldialogues.in/news/health/hospital-diagnostics/alleged-delay-of-6-years-in-cardiac-surgery-nhrc-issues-notice-to-centre-delhi-aiims-130368

New Delhi: The NHRC has taken suo motu cognisance of a media report published on June 13, which highlighted the case of a six-year-old boy from Begusarai awaiting cardiac surgery since 2019 when he was only three months old. Consequently, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Union Health Ministry and All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi.

The NHRC has issued notices to the Union Health Ministry and the AIIMS Delhi chief over reports alleging that a six-year-old boy from Bihar has been waiting for a cardiac issue-related surgery since 2019 when he was just three months old, officials said on Wednesday. According to the reports, AIIMS Delhi has cited various reasons for the delay, including bed unavailability and doctor's absence. The institute has formed a committee to investigate the allegations, as per NHRC's statement. According to a PTI report, the rights panel said it has taken suo motu cognisance of a media report, carried on June 13, that a six-year-old boy from Begusarai has been waiting for a cardiac issue-relate surgery since 2019 when he was three months old.

Doctors at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi have only been "providing dates" for the surgery on every visit by his family, the statement said. The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a very serious issue of violation of human rights. "The right to health and medical care is a basic human right. The AIIMS is one of the prestigious and premier public-funded healthcare institutions where a large number of people visit daily from across the country in the hope of getting their loved ones treated for their ailments by the best doctors of the nation," the statement said.

and Family Welfare, and the director of AIIMS-Delhi, seeking a detailed report within one week, including the present health status of the boy and a scheduled date of his cardiac surgery reportedly required and advised by the AIIMS's doctors, the statement said. As mentioned in the news report, the father of the boy earns a modest monthly income of Rs 8,000 and faces significant financial strain due to medical expenses as each visit to Delhi costs him between Rs 13,000 and Rs 15,000 for transportation and accommodation. The child cannot walk more than 15 steps without experiencing breathlessness. Additionally, his physical development has been hindered, the statement said.

Rights watchdog chief calls for improvement in refugee living conditions on World Refugee Day

https://www.msn.com/en-us/news/world/rights-watchdog-chief-calls-for-improvement-in-refugee-living-conditions-on-world-refugee-day/ar-BB1oxLpQ?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1

rights watchdog-refugee

SEOUL, June 20 (Yonhap) -- The chief of the National Human Rights Commission called Thursday for a revision of the Refugee Act to improve living conditions of those granted refugee status in the country.

Song Doo-hwan, chairman of the commission, made the statement marking World Refugee Day, saying the refugee problem is a joint responsibility shared by the international community and protecting their rights is an obligation.

"In many cases, those who apply for refugee status are faced with unstable legal status for a lengthy period due to backlog of cases up for evaluation, and they go on living under economic difficulties," Song said.

"Even if they are granted refugee status, relevant law makes them off limits to social security, unable to receive the treatment as inscribed by law," he added.

Under the Refugee Act, a foreigner staying in the country after being granted refugee status shall receive the same extent of social security as a South Korean citizen.

In reality, however, only people with resident registration can receive housing support offered to the vulnerable class, or get help in renting existing housing with jeonse, a unique rental system, under relevant work guidelines.